al growth rate of foodgrains in the Eighth Five Year Plan has been of the order of 2.6% which is higher than that of the natural population growth rate of 1.9%.

(b) The reasons for not achieving the targets for Eighth Five Year Plan are as under:

(i) Physical targets set for the Five Year Plan were not commensurate with financial resources made available in the Plan outlays.

(ii) The funding for the irrigation sector with respect to total State Plan size has steadily been declining from the Fifth Plan onwards. Against the share of irrigation sector as 23.25% in the Fifth Plan and 20.85% in the Sixth, it was 15.00% in the Eighth Plan.

(iii) Consequent to thin spreading of resources, time and cost-over-runs, out of the 158 major and 2267 medium projects spilling over from previous plan into Eighth Plan only 11 major and 34 medium projects are anticipated to have been completed during the Eight Plan.

(c) In order to increase production of various crops, the Government is implementing crop specific centrally sponsored schemes/programmes under which incentives are provided to farmers for use of quality seeds and location specific high yielding/hybrid varieties, application of integrated pest management, propagation of scientific water management including micro irrigation, improved farm implements etc. Besides, field demonstration on farmers' holdings inculding training of farmers and farm labourers are organised for effective transfer of technology. Further, under the national agenda for governance, the Government has given fresh thrust to double the food production in next ten years through adoption of regionally differentiated growth strategies, creation of farming infrastructure and more efficient use of resources.

Joint Ventures in Deep Sea Fishing

1733. SHRI K.R. MALKANI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that joint ventures have been forbidden from deep sea fishing as reported in the Financial Express, of the 10th September, 1996; and

(b) whether that will not leave deep sea fishing to foreign trawles, posing a threat to national security?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) No, Sir. However, a decision has been taken to rescind the New Deep Sea Fishing Policy of 1991 in September, 1996, on the recommendations of the Review Committee and no new permits, extension or renewal of permits have been issued thereafter.

(b) The Coast Guard and Navy are there to safeguard the national security and also illegal fishing by foreign fishing vessels.

फल उत्पादन

1734. **प्रो॰ रामबक्ष सिंह वर्मा:**
श्रीमती मालती शर्मा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सबसे अधिक फल उत्पादन करने वाला राज्य कौन-सा है;

(ख) क्या सरकार अन्य राज्यों में फलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) वर्ष 1995-96 के लिए उपलब्ध फल उत्पादन संबंधी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में आन्ध्र प्रदेश फल उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य है, जिसका वार्षिक उत्पादन 5.47 मिलियन मीटरी टन था।

(ख) और (ग) देश में सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को कवर करते हुए, सरकार उष्णकटिबंधी शीतोष्ण एवं शुष्क क्षेत्र में फलों के विकास की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम क्रियान्वित कर रही है। आठवीं योजना के दौरान स्कीम के लिए 74.30 करोड़ रुपये का परिव्यय था। स्कीम को 25.00 करोड रुपये के परिव्यय से

1998-99 में जारी रखा जा रहा है। इस स्कीम के तहत, क्वालिटी की पौध सामग्री के वितरण हेतु नर्सरियों एवं टिश्यू कल्चर यूनिटों की स्थापना, क्षेत्र विस्तार, जीर्ण बागानों के नवीकरण, किसानों के प्रशिक्षण एवं प्रसार उपाय करने हेतु सहायता प्रदान की जा रही है।

डी०एम०एस० को घाटा

1735. **श्री बलवन्त सिंह रापूवालियां:**
श्री राज मोहिन्दर सिंह:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना (डी०एम०एस०) को पिछले कुछ वर्षों से लगातार घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1998 तक डी०एम०एस० को कुल कितना घाटा हुआ है; और

(ग) इस योजना के संचालन के लिए विभिन्न स्रोतों के माध्यम से मार्च, 1998 तक डी०एम०एस० में कुल कितना पूंजी-निवेश किया गया था?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली दुग्ध योजना को मार्च, 1998 तक कुल 401.94 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। यह राशि मार्च, 1992 तक के लेखा परीक्षित प्रोफार्मा लेखों पर आधारित है और उसके बाद अनन्तिम लेखों पर आधारित है। दिल्ली दुग्ध योजना को कृषि मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) की अनुदान मांगों के हिसाब से सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष योजना और गैर-योजना खर्च के लिए निधि आवंटित की जाती है। इसमें अन्य किसी स्रोत के जरिए पूंजी निवेश का कोई प्रावधान नहीं है। दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा अर्जित धनराशि को भारत की संचयी निधि में जमा कर दिया जाता है। व्यय और प्राप्त राजस्व के बीच जो अंतर होता है उसे सरकार द्वारा बजटीय समर्थन के रूप में प्रदान किया जाता है।

प्याज का भंडारण

1736. **श्री रमा शंकर कौशिक:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998 के दौरान प्याज का कुल कितना उत्पादन हुआ था;

(ख) सरकार द्वारा घरेलू खपत के लिए प्याज की कितनी मात्रा का भंडारण किया गया है;

(ग) क्या सरकार प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) 1998-99 के दौरान प्याज का उत्पादन 4.72 मिलियन टन तक होने का अनुमान है।

(ख) भारत सरकार की प्याज के भण्डारण की कोई स्कीम नहीं है।

(ग) और (घ) पहली फरवरी, 1999 को प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटा लिया गया और बंगलौर रोज प्याज तथा कृष्णापुरम प्याज के निर्यात की अनुमति दी गई। सरकार से सरकार को माल भेजने के आधार पर श्रीलंका को 3,000 मीटरी टन प्याज का निर्यात करने की दोनों सरकारों की पारस्परिक अनुमति भी प्रदान की गई। 12 फरवरी, 1999 को सम्पर्क एजेंसियों के जरिये अगले तीन महीनों के लिए 25,000 मीटरी टन प्याज प्रति माह निर्यात करने की अनुमति भी अधिसूचित की गई।

Special scheme to modernise agriculture

1737. SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the details of special scheme to modernise agriculture in all the States and Gujarat in particular in order to make them self sufficient in production of foodgrains;

(b) the steps taken to provide high yielding variety of seeds and fertilizers in time and at cheaper rates;

(c) whether consumption and availability of fertilizers in Gujarat is less than other States; and

(d) if so, the remedial measure taken by Government in this regards?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) A number of Central/Centrally Sponsored Schemes are being implemented by Union Government for the development of agriculture, as also to supplement the efforts of the State Governments for increasing the productivity and production of food-